

राष्ट्रीय हिन्दी साप्ताहिक

स्वतंत्र प्रभात

जो लिखेगा, वही टिकेगा



@swatantraprabhatmedia



@swatantramedia

RNI.No. (UHN/2009/34814) (epaper.swatantraprabhat.com)



@SwatantraPrabhatonline



news@swatantraprabhat.com

सीतापुर से प्रकाशित एवं अयोध्या, प्रयागराज, मिर्जापुर, गोरखपुर, बरेली, बुंदेलखंड, उत्तराखंड, देहरादून

सीतापुर, बुधवार, 15 अक्टूबर 2025

वर्ष 16, अंक 59, पृष्ठ 04, मूल्य: 01 रुपया

www.swatantraprabhat.com

गाजियाबाद, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, झारखण्ड, बिहार, मध्य प्रदेश, असम, तेलंगाना आदि जनपदों में प्रसारित

इंडस्ट्री एरिया में छापा, 7.37 लाख का वेज फैट सीज किया..04



स्वतंत्र प्रभात दैनिक अख़बार तथा ऑनलाइन चैनल से सीधा जुड़ने के लिए संपर्क करें.....
9511151254

ग़्राह्यचारियों को बचाने में लगे डीपीआरओ..03

क्या न्यायिक अधिकारी सीधी भर्ती से बन सकते हैं जिला जज? - सुप्रीम कोर्ट

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

क्या बार में पहले ही 7 साल पूरे करने वाले न्यायिक अधिकारी जिला जज बन सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इस सवाल का जवाब दे दिया है. कोर्ट ने कहा है कि बार में पहले ही 7 साल पूरे करने वाले न्यायिक अधिकारी जिला जज बन सकते हैं. सर्वोच्च अदालत ने कहा कि वे न्यायिक अधिकारी बार कोटे के तहत जिला जज बनने के पात्र हैं. अतिरिक्त जिला जज के लिए पात्रता पर कोर्ट ने कहा कि संविधान की व्याख्या सहज होनी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला जिला जजों की सीधी भर्ती के लिए न्यायिक अधिकारियों की पात्रता पर दिया है. CJI बीआर गवई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने ये फैसला सुनाया. 25 सितंबर को संविधान पीठ ने फैसला सुनिश्चित रखा था. पीठ में 3 दिनों तक सुनवाई चली थी. बार कोर्ट के तहत जिला जजों के पद के लिए न्यायिक अधिकारियों की पात्रता से जुड़ा मामला है. CJI ने कहा कि हमने सभी निर्णयों पर विचार किया है और पाया है कि रमेश्वर दयाल और चंद्र मोहन के निर्णयों पर अन्य मामलों में उचित विचार नहीं किया गया है. अनुच्छेद 233 को संपूर्ण रूप से पढ़ा जाना चाहिए. इसे आंशिक रूप से नहीं पढ़ा जा सकता. उन्होंने कहा कि व्याख्या पांडित्यपूर्ण नहीं हो सकती. यह स्वाभाविक होनी चाहिए. कोई भी व्याख्या जो प्रतिस्पर्धा को

साक्षिप्त ख़बरें

2.7 लाख की ठगी; हष्ट कैडेट को दिया सेना में भर्ती का झांसा, मेडिकल और रनिंग करवाई फिर थमा दिया फर्जी जॉइनिंग लेटर



महराजगंज- जिले के निचलौल थाना क्षेत्र से एक चौकाने वाला मामला सामने आया है, जहां सेना में भर्ती का सपना दिखाकर एक 12वीं की छात्रा से 2.7 लाख रुपये ठग लिए गए। छात्रा एनसीसी कैडेट है और सेना में जाने का सपना देख रही थी। आरोपियों ने छात्रा को झ्रासे में लेकर उससे फर्जी मेडिकल और रनिंग करवाई। यहां तक कि उसे सेना की नकली वर्दी प्रमाणक फर्जी जॉइनिंग लेटर भी दे दिया। डोमा गांव की रहने वाली नागमा नाम की छात्रा कृष्क इंटर कॉलेज में 12वीं की पढ़ाई कर रही है और एनसीसी कैडेट भी है। अगस्त महीने में वह एनसीसी की ट्रेनिंग के लिए मउलार, सलेमपुर गई थी। वहीं उसकी मुलाकात धीरज नाम के एक युवक से हुई। धीरज ने नागमा से कहा कि वह उसे सेना में भर्ती करवा सकता है। सितंबर में धीरज ने नागमा को गोरखपुर बुलाया। वहां उसे सेना की वर्दी दी गई और फिर एक फील्ड में ले जाकर लौड़ (रनिंग) कराई गई। वहां पहले से कुछ और लड़कें-लड़कियां भी मौजूद थे। इसके बाद उसका फर्जी मेडिकल टेस्ट कराया गया।

2.70 लाख रुपये की मांग
इन फर्जी प्रक्रियाओं के बाद धीरज ने नागमा से 2 लाख 70 हजार रुपये मांगे। पैसे देने के बाद नागमा को राजस्थान के पुष्कर ले जाया गया, जहां अंगद मिश्रा नाम के एक शख्स से मिलवाया गया। अंगद ने भरोसा दिलाया कि पैसे के बाद उसे जॉइनिंग लेटर मिल जाएगा। पैसे देने के बाद नागमा को एक जॉइनिंग लेटर दिया गया और वह घर लौट आई। गांव में उसे सेना में चर्चनित मानकर फूल-मालाओं से स्वागत किया गया और देशभक्ति गानों के साथ पूरे गांव में घुमाया गया। लेकिन जब परिजनों ने जॉइनिंग लेटर की जांच कराई, तो पता चला कि वह फर्जी है। सच्चाई सामने आने पर नागमा ने धीरज और अंगद मिश्रा के खिलाफ निचलौल थाने में केस दर्ज कराया है। पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है।

प्रतिबंधित करती है, स्वीकार नहीं की जाएगी.

राज्य सरकार को सेवारत उम्मीदवारों के लिए पात्रता सुनिश्चित करने वाले नियम बनाने होंगे. नियमों में यह प्रावधान होना चाहिए कि सेवारत उम्मीदवार तभी पात्र होगा जब उसके पास न्यायिक अधिकारी और अधिवक्ता के रूप में कुल मिलाकर 7 वर्ष का अनुभव हो. पीठ ने कहा कि हमने इस तर्क को खारिज कर दिया है कि धारा 233(2) सीधी भर्ती के लिए 25% कोटा प्रदान करती है. स्टोरे डेसिसिस का सिद्धांत गलत कानून की अनुमति नहीं दे सकता. हमने माना है कि न्यायिक सेवा के सदस्यों के साथ अन्याय हुआ है. कोर्ट ने कहा कि हमने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय केवल निर्णय की तिथि से ही लागू होगा. सिवाय उन मामलों के जहां हाई कोर्ट द्वारा कोई अंतरिम आदेश पारित किया गया हो. अदालत ने कहा कि न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति होने पर अधिवक्ता का केवल प्रैक्टिस करने का अधिकार निलंबित हो जाता है और उसका नाम रोल में बना रहता है. जिन न्यायिक अधिकारियों ने भर्ती से पहले ही बार में 7 वर्ष पूरे कर लिए हैं, वे सीधी भर्ती में जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के पात्र होंगे. आवेदन के समय पात्रता देखी जानी है. हालांकि धारा 233 में कोई पात्रता निर्धारित नहीं है, फिर भी समान अवसर प्रदान करने के लिए हमने कहा है कि उम्मीदवार के पास अधिवक्ता और न्यायिक अधिकारी के रूप में संयुक्त रूप से 7 वर्ष का

अनुभव होना चाहिए. आवेदन की तिथि को न्यूनतम आयु 35 वर्ष होगी. कोर्ट ने आगे कहा कि सभी नियम जो निर्णय के अनुरूप नहीं हैं, रद्द माने जाएंगे. नए नियम बनाए जाएंगे।

अपने आदेश में सीजीआई ने क्या-क्या कहा?

CJI ने कहा कि राज्य सरकारों को उच्च न्यायालयों के परामर्श से जिला न्यायाधीश के पद पर आवेदन करने वाले न्यायिक अधिकारियों के लिए नियम बनाने होंगे।

CJI ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति 5 साल तक वकालत करता है और 10 साल का ब्रेक लेता है और फिर 2 साल तक वकालत करता है, तो वह पूरी तरह से वकालत से अलग हो जाएगा

CJI ने कहा कि न्यायिक अधिकारियों को सीधी भर्ती के माध्यम से जिला जज के रूप में नियुक्त करने से बचत करके उनके साथ अन्याय किया गया है।

CJI ने कहा कि फैसला केवल फैसले की तिथि से लागू होगा और फैसले से पहले किए गए आवेदनों या चर्चनों को प्रभावित नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेवा में आने से पहले 7 साल की कानूनी सेवा पूरी कर चुके न्यायिक अधिकारी जिला जज के रूप में नियुक्त होने के हकदार होंगे. नियुक्ति के लिए पात्रता पर चयन के समय विचार किया जाएगा।

पंजाब- टीवी कार्यक्रम के दौरान वाल्मीकि पर टिप्पणी के लिए अंजना ओम कश्यप पर केस दर्ज

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

नई दिल्ली- लुधियाना पुलिस ने आजतक की एंकर अंजना ओम कश्यप के खिलाफ एक टीवी डिवेट के दौरान वाल्मीकि का कथित रूप से अपमान करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की है. गुरुवार को दर्ज की गई एफआईआर में इंडिया टुडे समूह के अध्यक्ष और प्रधान संपादक अरुण पुरी और लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड को भी आरोपी बनाया गया है. द फ्रंट की रिपोर्ट के अनुसार, यह एफआईआर भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज भावदास के राष्ट्रीय संयोजक चौधरी यशपाल की शिकायत पर दर्ज की गई है, जिसके अध्यक्ष विजय दानव हैं. एफआईआर के अनुसार, कश्यप ने एक टीवी शो के दौरान वाल्मीकि के बारे में बात करते हुए 'अनुचित' भाषा का इस्तेमाल किया था, जिसका प्रसारण मंगलवार को चैनल के आधिकारिक सोशल मीडिया पेजों पर किया गया था. एफआईआर में उद्धृत शिकायत में कहा गया है, 'इन बयानों से पूरे वाल्मीकि समुदाय की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंची है और इससे पहले कि यह मामला कानून-व्यवस्था का मुद्दा बने, एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए.' शिकायत में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का भी हवाला दिया गया है, जिसमें दावा किया गया है कि उसने भगवान वाल्मीकि की पवित्रता और अच्छई को बरकरार रखा है।

चौधरी यशपाल ने कहा है कि समुदाय कश्यप की गिरफ्तारी चाहता है. उन्होंने कहा, 'हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक



आरोपी सलाखों के पीछे न पहुंच जाएं. हमने अपने समुदाय से इस मुद्दे पर एकजुट होने का आह्वान किया है.' भारतीय न्याय सहिता (बीएनएस) 2023 की धारा 299 (किसी वर्ग के नागरिकों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के इरादे से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्यों को दंडित करना, मौखिक या लिखित शब्दों, संकेतों, दृश्य चित्रण या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से उनके धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है. एफआईआर में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 3 (1)(V) का भी उल्लेख किया गया है, जो इन समुदायों के भूमि अधिकारों से संबंधित है।

वाल्मीकि एक प्रख्यात कवि थे जिन्होंने रामायण की रचना की थी. उन्हें 'आदि कवि', यानी प्रथम कवि भी कहा जाता है. उनके अनुयायियों को 'बाल्मीकि' कहा जाता है और वे प्रमुख दलित समुदाय में गिने जाते हैं. शिकायत कश्यप के मंगलवार (7 अक्टूबर) को प्रसारित ब्लैक एंड व्हाइट शो से संबंधित है, जिसमें हाल ही में एक वकील द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई

पराली जलाने लेकर CM योगी के सख्त निर्देश सेटेलाइट से निगरानी, किसानों को करें जागरूक

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

उत्तर प्रदेश में पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर सख्त रुख अपनाया है. मुख्यमंत्री ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में पराली जलाने की घटनाओं को रोक दिया जाए. इस संबंध में शासनादेश के तहत विस्तृत दिशा-निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं. मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि पराली जलाने से पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता है और जनस्वास्थ्य पर भी गंभीर प्रभाव पड़ता है. इसलिए किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के वैकल्पिक उपायों के प्रति जागरूक किया जाए. सभी जिलाधिकारियों से अपेक्षा की

जिलाधिकारियों से कहा गया है कि हॉटस्पॉट चिन्हित करते हुए 50/100 किसानों पर एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति किया जाए. नोडल अधिकारी को पराली जलाने की घटनाओं को शून्य करने के लिए विशेष हिदायत दी जाए. इसके साथ ही, राजस्व, पुलिस, कृषि, ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज विभागों के जनपद, तहसील, विकासखण्ड एवं क्षेत्रीय कमियों के माध्यमसे फसल कटने के समय निगरानी करते हुए, फसल अवशेष जलाने की घटनाओं को शून्य करना है. यदि कोई किसानों पर एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी जो पराली जलाने की घटनाओं की रोकथाम सुनिश्चित करेंगे. **नोडल अधिकारी की नियुक्ति का आदेश**

जिलाधिकारियों से कहा गया है कि हॉटस्पॉट चिन्हित करते हुए 50/100 किसानों पर एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति किया जाए. नोडल अधिकारी को पराली जलाने की घटनाओं को शून्य करने के लिए विशेष हिदायत दी जाए. इसके साथ ही, राजस्व, पुलिस, कृषि, ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज विभागों के जनपद, तहसील, विकासखण्ड एवं क्षेत्रीय कमियों के माध्यमसे फसल कटने के समय निगरानी करते हुए, फसल अवशेष जलाना हुआ पाया जाता है तो मौके पर उसको रोकना तथा उस पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि अधिरोपित करते हुए कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सज़ा की समयसीमा तय करने की केंद्र सरकार की याचिका ख़ारिज की

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

नई दिल्ली- सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (8 अक्टूबर) को केंद्र सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें मौत की सज़ा पाए दोषियों के लिए कानूनी उपायों का लाभ उठाने हेतु सख्त समयसीमा और दया याचिका खारिज करने के सात दिनों के भीतर फांसी देने की मांग की गई थी. केंद्र सरकार का पक्ष सुनने के बाद जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनबी अंजारिया की पीठ ने कहा कि इस याचिका में कोई दम नहीं है. हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने फैसला सुनाया कि 2014 का शत्रुघ्न चौहान फैसला, जिसमें केंद्र सरकार संशोधन चाहती है, सभी पहलुओं से पूर्ण है. याचिका में 2014 के फैसले में कुछ संशोधनों की मांग की गई थी. इसके पीछे तर्क यह दिया गया था कि यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि मृत्युदंड के मामलों की रूपरेखा में पीड़ितों के अधिकारों और पीड़ा को ध्यान में रखा जाए और दोषियों के सामने लंबे समय से चली आ रही अनिश्चितता का भी समाधान किया जाए. 2014 के फैसले में संशोधन करने से इनकार

पहले डिमोशन, अब कानपुर के करोड़पति लेखपाल आलोक दूबे की और बड़ी मुश्किलें, हुआ ये एक्शन

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

कानपुर में करोड़पति कानूंगो मामले में पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए कानूंगो समेत 7 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है. इसमें एक महिला लेखपाल भी शामिल है. आरोपी कानूंगो आलोक दुबे को डीएम ने पहले ही डिमोशन करके लेखपाल बना दिया है. अब सभी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल होने के बाद राजस्व विभाग में हड़कंप मचा हुआ है. जिले में जमीन विवाद से जुड़ा एक बड़ा फर्जीबाड़ा उजागर हुआ था, जिसमें कानूंगो से डिमोट करके लेखपाल बने आलोक दुबे समेत सात लोगों के खिलाफ मुनि से मिलने पर वाल्मीकि का हृदय परिवर्तन हुआ और वे भगवान राम के भक्त बन गए. वह कहती हैं कि इस कहानी ने एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया कि सांठगाट आत्मसाक्षात्कार और आत्मनिरीक्षण का एक क्षण भी सबसे बुरे प्राणी का जीवन बदल सकता है. हालांकि, यशपाल का कहना है कि वाल्मीकि के जीवन से जुड़ी कहानियां ऐतिहासिक रूप से सत्य नहीं हैं. उन्होंने कहा, 'महापुराणों के जीवन से जुड़ी कितनी ही कहानियां लोककथाओं का हिस्सा बन जाती हैं. इनके सच होने का कोई प्रमाण नहीं है. एंकर को उस व्यक्ति के बारे में एक बेबुनियाद कहानी सुनाने की ब्या जरूरत थी जिसे हम अपना भावना मानते हैं.' उन्होंने कहा, 'महापुराणों के जीवन से जुड़ी कितनी ही कहानियां लोककथाओं का हिस्सा बन जाती हैं. इनके सच होने का कोई प्रमाण नहीं है. एंकर को उस व्यक्ति के बारे में एक बेबुनियाद कहानी सुनाने की ब्या जरूरत थी जिसे हम अपना भावना मानते हैं.' उन्होंने कहा, 'महापुराणों के जीवन से जुड़ी कितनी ही कहानियां लोककथाओं का हिस्सा बन जाती हैं. इनके सच होने का कोई प्रमाण नहीं है.

यह विवाद सचेंडी थाना क्षेत्र के कला का पुरवा से जुड़ा है. निवासी संदीप सिंह ने तहसीर देकर आरोप लगाया कि स्व. गंगा सिंह के हिस्से की भूमि पर फर्जी रजिस्ट्री कराई गई. वादी की मां मोहनलाल उर्फ लाल साहिबा ने पहले ही अपने पति के हिस्से की जमीन का कुछ भाग वसीयत और कुछ भाग दानपत्र के माध्यम से हस्तांतरित कर दिया था. इसके

बरेली में ये क्या हो रहा है? क्यों मुस्लिम परिवार लगा रहे आई लव योगी-मोदी के नारे? एक नोटिस और बदल गया सबकुछ

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

बरेली- उत्तर प्रदेश के बरेली शहर की फिजा अब बदल चुकी है, जहां पहले आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद को लेकर तनाव फैला हुआ था. वहीं अब कुछ परिवार आई लव योगी और आई लव मोदी कह रहे हैं. बीते 26 सितंबर को हुई हिंसा के बाद से शासन-प्रशासन सख्त रवैया अपना रहा है, किसानों पर एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति किया जाए. नोडल अधिकारी को पराली जलाने की घटनाओं को शून्य करने के लिए विशेष हिदायत दी जाए. इसके साथ ही, राजस्व, पुलिस, कृषि, ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज विभागों के जनपद, तहसील, विकासखण्ड एवं क्षेत्रीय कमियों के माध्यमसे फसल कटने के समय निगरानी करते हुए, फसल अवशेष जलाने की घटनाओं को शून्य करना है. यदि कोई कृषक फसल अवशेष जलाता हुआ पाया जाता है तो मौके पर उसको रोकना तथा उस पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि अधिरोपित करते हुए कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

नगर निगम की नोटिस से बदला हाल
बता दें कि बरेली में अवैध कब्जेदारों पर पुलिस और प्रशासन की ताबड़तोड़ कार्रवाई के बाद अब मुस्लिम परिवारों ने आई लव योगी और आई लव मोदी कहकर



स्वतंत्र प्रभात दैनिक अख़बार तथा ऑनलाइन चैनल से सीधा जुड़ने के लिए संपर्क करें.....

9511151254

@SwatantraPrabhatonline

news@swatantraprabhat.com

गाजियाबाद , दिल्ली , हरियाणा , चंडीगढ़ , झारखण्ड , बिहार , मध्य प्रदेश , असम, तेलंगाना आदि जनपदों में प्रसारित

इंडस्ट्री एरिया में छापा, 7.37 लाख का वेज फ़ैट सीज किया..04

बाद मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा आधी रात को उनकी अंतिम याचिका खारिज करने के बाद उन्हें फांसी दे दी गई. अख़बार के अनुसार, केंद्र सरकार ने अपने आवेदन में कहा कि शत्रुघ्न चौहान मामले में फैसला, दोषियों को अत्यधिक देरी से बचाते हुए, 'पीड़ितों और उनके परिवार के सदस्यों के अप्रूपीय मानसिक आघात, पीड़ा, उथल-पुथल और विक्षिप्तता को ध्यान में नहीं रखता है.' आवेदन में कहा गया है कि आतंकवाद, बलात्कार और हत्या जैसे जघन्य अपराधों के दोषी अनुच्छेद 21 (जीवन के अधिकार) की आड़ में 'न्यायिक प्रक्रिया को धोखा देते हैं.' अपने आवेदन में केंद्र ने अदालत से यह घोषित करने का आग्रह किया कि सभीथा याचिका खारिज होने के बाद उपचारात्मक याचिकाएं केवल एक निर्धारित समय के भीतर ही दायर की जानी चाहिए. इसके अलावा इसमें यह स्पष्टीकरण भी मांगा गया कि मृत्यु वारंट जारी होने के सात दिनों के भीतर दया याचिका दायर की जानी चाहिए. अंत में आवेदन में यह निर्देश देने की मांग की गई कि दया याचिका खारिज होने के सात दिनों के भीतर फांसी दे दी जाए, चाहे सह-दोषियों की कार्यवाही लंबित हो या नहीं।

करते हुए अदालत ने केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) केएम नटराज से कहा कि वह उचित कार्यवाही में अपने आवेदन में जिन उपायों पर जोर दे रही है, उनमें से कुछ को लागू करने के लिए स्वतंत्र है. एएसजी नटराज ने 24 सितंबर को अदालत को बताया था, 'सरकार होने के सात दिनों के भीतर फांसी देने की मांग की गई थी. केंद्र सरकार का पक्ष सुनने के बाद जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनबी अंजारिया की पीठ ने कहा कि इस याचिका में कोई दम नहीं है. हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने फैसला सुनाया कि 2014 का शत्रुघ्न चौहान फैसला, जिसमें केंद्र सरकार संशोधन चाहती है, सभी पहलुओं से पूर्ण है. याचिका में 2014 के फैसले में कुछ संशोधनों की मांग की गई थी. इसके पीछे तर्क यह दिया गया था कि यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि मृत्युदंड के मामलों की रूपरेखा में पीड़ितों के अधिकारों और पीड़ा को ध्यान में रखा जाए और दोषियों के सामने लंबे समय से चली आ रही अनिश्चितता का भी समाधान किया जाए. 2014 के फैसले में संशोधन करने से इनकार

बाबजूद राजपति देवी और राजकुमारी देवी ने संपूर्ण भूमि पर दावा करते हुए रजिस्ट्री करा ली.

नहीं हुआ चैक से भुगतान
शेष भूमि R N G इंफ्रा के भागीदार अमित गर्ग के नाम रजिस्टर्ड अनुबंध से हस्तांतरित की गई. जांच के दौरान यह भी सामने आया कि रजिस्ट्री में जिन चेक नंबरों का उल्लेख बना दिया है. अब सभी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल होने के बाद राजस्व विभाग में हड़कंप मचा हुआ है. जिले में जमीन विवाद से जुड़ा एक बड़ा फर्जीबाड़ा उजागर हुआ था, जिसमें कानूंगो से डिमोट करके लेखपाल बने आलोक दुबे और तत्कालीन लेखपाल अरुणा द्विवेदी ने यह जानते हुए भी कि विवादित भूमि खतौनी में राजपति और राजकुमारी के नाम दर्ज नहीं है, फर्जी दस्तावेज तैयार कराए. उन्होंने न्यायालय को धोखे में रखकर नाम चढ़ाने का आदेश कराया और उसी दिन रजिस्ट्री भी कराई. अगर जिलाधिकारी (वि/रा) की निस्सरीय जांच रिपोर्ट में दोनों पर अनुचित लाभ पहुंचाने का आरोप सिद्ध हुआ. विवेचक ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि यह अपराध लोक सेवकों द्वारा पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में नहीं बल्कि निजी स्वार्थ के लिए किया गया, अमन सेंगर, देवत इंड्रा के भागीदार अमित गर्ग, तत्कालीन लेखपाल अरुणा द्विवेदी और तत्कालीन कानूंगो आलोक दुबे शामिल हैं.

मामला कैसे शुरू हुआ
यह विवाद सचेंडी थाना क्षेत्र के कला का पुरवा से जुड़ा है. निवासी संदीप सिंह ने तहसीर देकर आरोप लगाया कि स्व. गंगा सिंह के हिस्से की भूमि पर फर्जी रजिस्ट्री कराई गई. वादी की मां मोहनलाल उर्फ लाल साहिबा ने पहले ही अपने पति के हिस्से की जमीन का कुछ भाग वसीयत और कुछ भाग दानपत्र के माध्यम से हस्तांतरित कर दिया था. इसके

बरेली में ये क्या हो रहा है? क्यों मुस्लिम परिवार लगा रहे आई लव योगी-मोदी के नारे? एक नोटिस और बदल गया सबकुछ

बाद मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा आधी रात को उनकी अंतिम याचिका खारिज करने के बाद उन्हें फांसी दे दी गई. अख़बार के अनुसार, केंद्र सरकार ने अपने आवेदन में कहा कि शत्रुघ्न चौहान मामले में फैसला, दोषियों को अत्यधिक देरी से बचाते हुए, 'पीड़ितों और उनके परिवार के सदस्यों के अप्रूपीय मानसिक आघात, पीड़ा, उथल-पुथल और विक्षिप्तता को ध्यान में नहीं रखता है.' आवेदन में कहा गया है कि आतंकवाद, बलात्कार और हत्या जैसे जघन्य अपराधों के दोषी अनुच्छेद 21 (जीवन के अधिकार) की आड़ में 'न्यायिक प्रक्रिया को धोखा देते हैं.' अपने आवेदन में केंद्र ने अदालत से यह घोषित करने का आग्रह किया कि सभीथा याचिका खारिज होने के बाद उपचारात्मक याचिकाएं केवल एक निर्धारित समय के भीतर ही दायर की जानी चाहिए. इसके अलावा इसमें यह स्पष्टीकरण भी मांगा गया कि मृत्यु वारंट जारी होने के सात दिनों के भीतर दया याचिका दायर की जानी चाहिए. अंत में आवेदन में यह निर्देश देने की मांग की गई कि दया याचिका खारिज होने के सात दिनों के भीतर फांसी दे दी जाए, चाहे सह-दोषियों की कार्यवाही लंबित हो या नहीं।

बाबजूद राजपति देवी और राजकुमारी देवी ने संपूर्ण भूमि पर दावा करते हुए रजिस्ट्री करा ली.

नहीं हुआ चैक से भुगतान
शेष भूमि R N G इंफ्रा के भागीदार अमित गर्ग के नाम रजिस्टर्ड अनुबंध से हस्तांतरित की गई. जांच के दौरान यह भी सामने आया कि रजिस्ट्री में जिन चेक नंबरों का उल्लेख बना दिया है. अब सभी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल होने के बाद राजस्व विभाग में हड़कंप मचा हुआ है. जिले में जमीन विवाद से जुड़ा एक बड़ा फर्जीबाड़ा उजागर हुआ था, जिसमें कानूंगो से डिमोट करके लेखपाल बने आलोक दुबे और तत्कालीन लेखपाल अरुणा द्विवेदी ने यह जानते हुए भी कि विवादित भूमि खतौनी में राजपति और राजकुमारी के नाम दर्ज नहीं है, फर्जी दस्तावेज तैयार कराए. उन्होंने न्यायालय को धोखे में रखकर नाम चढ़ाने का आदेश कराया और उसी दिन रजिस्ट्री भी कराई. अगर जिलाधिकारी (वि/रा) की निस्सरीय जांच रिपोर्ट में दोनों पर अनुचित लाभ पहुंचाने का आरोप सिद्ध हुआ. विवेचक ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि यह अपराध लोक सेवकों द्वारा पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में नहीं बल्कि निजी स्वार्थ के लिए किया गया, अमन सेंगर, देवत इंड्रा के भागीदार अमित गर्ग, तत्कालीन लेखपाल अरुणा द्विवेदी और तत्कालीन कानूंगो आलोक दुबे शामिल हैं.

मामला कैसे शुरू हुआ
यह विवाद सचेंडी थाना क्षेत्र के कला का पुरवा से जुड़ा है. निवासी संदीप सिंह ने तहसीर देकर आरोप लगाया कि स्व. गंगा सिंह के हिस्से की भूमि पर फर्जी रजिस्ट्री कराई गई. वादी की मां मोहनलाल उर्फ लाल साहिबा ने पहले ही अपने पति के हिस्से की जमीन का कुछ भाग वसीयत और कुछ भाग दानपत्र के माध्यम से हस्तांतरित कर दिया था. इसके



स्वतंत्र प्रभात दैनिक अख़बार तथा ऑनलाइन चैनल से सीधा जुड़ने के लिए संपर्क करें.....

9511151254

@SwatantraPrabhatonline

news@swatantraprabhat.com

गाजियाबाद , दिल्ली , हरियाणा , चंडीगढ़ , झारखण्ड , बिहार , मध्य प्रदेश , असम, तेलंगाना आदि जनपदों में प्रसारित

इंडस्ट्री एरिया में छापा, 7.37 लाख का वेज फ़ैट सीज किया..04

बाद मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा आधी रात को उनकी अंतिम याचिका खारिज करने के बाद उन्हें फांसी दे दी गई. अख़बार के अनुसार, केंद्र सरकार ने अपने आवेदन में कहा कि शत्रुघ्न चौहान मामले में फैसला, दोषियों को अत्यधिक देरी से बचाते हुए, 'पीड़ितों और उनके परिवार के सदस्यों के अप्रूपीय मानसिक आघात, पीड़ा, उथल-पुथल और विक्षिप्तता को ध्यान में नहीं रखता है.' आवेदन में कहा गया है कि आतंकवाद, बलात्कार और हत्या जैसे जघन्य अपराधों के दोषी अनुच्छेद 21 (जीवन के अधिकार) की आड़ में 'न्यायिक प्रक्रिया को धोखा देते हैं.' अपने आवेदन में केंद्र ने अदालत से यह घोषित करने का आग्रह किया कि सभीथा याचिका खारिज होने के बाद उपचारात्मक याचिकाएं केवल एक निर्धारित समय के भीतर ही दायर की जानी चाहिए. इसके अलावा इसमें यह स्पष्टीकरण भी मांगा गया कि मृत्यु वारंट जारी होने के सात दिनों के भीतर दया याचिका दायर की जानी चाहिए. अंत में आवेदन में यह निर्देश देने की मांग की गई कि दया याचिका खारिज होने के सात दिनों के भीतर फांसी दे दी जाए, चाहे सह-दोषियों की कार्यवाही लंबित हो या नहीं।

बात यह है कि इस मामले में सलिस आलोक दुबे को जिलाधिकारी ने पहले ही डिमोशन देकर कानूंगो से लेखपाल बना दिया था.

अवैध संपत्ति की होगी जांच
इसके अलावा, विजिलेंस विभाग आलोक दुबे की अलग से जांच कर रहा है, जिसमें उनकी करोड़ों रुपये की अवैध संपत्ति के संकेत मिले हैं. यह तथ्य मामले को और गंभीर बना देता है. सभी आरोपितों को भारतीय न्याय सहिता की धाराओं 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2), 352 और 351(3) के तहत अभियोग पाया गया है। पुलिस ने इन धाराओं के तहत गंभीर अपराध के साक्ष्य अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए हैं. अब आरोपी न्यायालय में अभियुक्त के रूप में पेश होंगे.

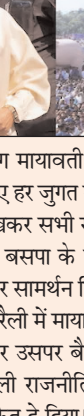
इसी साल दर्ज हुई थी FIR<

बसपा की रैली देख, विपक्षी दलों के छोटे पसीने

उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले सभी राजनीतिक दल धीरे-धीरे अपनी जोर आजादी में जुटे हैं। जहां भाजपा के लोग सरकार को योजना का बखान लोगों के बीच करते हुए फिर सत्ता के तरफ निगाह बनाये हैं, वहीं सपा भी पीडीए के मायाजाल को फैलाकर वोट बैंक को मजबूत करने पर जुटी है, रही बाक कांग्रेस की तो वह तो जानती है कि दिल्ली ही नहीं बल्कि लखनऊ भी बहुत दूर है। लेकिन इसी बीच बीते 12 वर्षों से राजनीतिक वनवास बीता रही बसपा की रैली ने एक बार फिर ठंडी शुरु होने के ठीक पहले राजनीतिक गालियारों में गंभी पैदा कर दी है। साथ ही चुनाव बाद 5वॉन बार यूपी में बसपा के सरकार की भविष्यवाणी ने सपा और भाजपा के कान खड़े कर दिये हैं जिसका प्रमाण लखनऊ में आयोजित बसपा की रैली में उमड़ी भारी भीड़ ने मुहर लगा दी। एक समय राष्ट्रीय राजनीत में बहुजन समाज पार्टी को 'गूँज दूर-दूर तक सुनाई देती थी, लेकिन गुजरते वक़्त के साथ बसपा राष्ट्रीय राजनीति से जैसे गायब हो हो गई। समय के साथ पार्टी का प्रभाव धीरे-धीरे सिमटता गया। लोकसभा और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में लगातार झटकों ने बसपा को हाशिए पर ला खड़ा किया। हालांकि बीते 9 अक्टूबर को लखनऊ में हुई मायावती की रैली में उमड़ी भारी भीड़ ने न सिर्फ पार्टी को नई ऊर्जा दी, बल्कि मायावती के आत्मविश्वास को भी फिर से जगा दिया है। यह भीड़ बताती है कि बसपा का जादू अब भी कायम है। अब यह देखा है कि यह भीड़ आगामी चुनावों में बसपा के राजनीतिक धारा में फिर से पुनर्रजीव करेगी? जिस तरह लखनऊ की रैली में लोगों की ऐतिहासिक भीड़ देखने को मिली, इससे फिर से बसपा की उल्टी-उल्टी जगह है कि बसपा और मायावती पर दलितों

का विश्वास कम नहीं हुआ है। दलितों के लिए आज भी मायावती बड़ी नेता हैं। यही कारण है कि लखनऊ रैली में जिस ऊँचाई से दलित सम्मिलित हुए हैं, उसने मायावती को भी लंबे वक्त बाद किसी राजनीतिक मंच पर खुश होने का मौका दे दिया है। इतनी भीड़ देखकर जहाँ बसपा में खुशी है वहीं विपक्षी दलों समाजवादी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस में डर भी बन गया है। लखनऊ की रैली में बसपा सुप्रीमो मायावती ने खुद कहा कि ये जो लाखों-लाखों की संख्या में लोग आए हुए हैं तो इनको यहाँ दूसरी पार्टियों की तरह दिहाड़ी पर नहीं लाया गया है, बल्कि ये लोग अपने खून पसीने की कमाई के पैसों से ही खुद चलकर आये हैं। लखनऊ यह रैली बसपा के लिए सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक संदेश भी था कि दलित समाज का भरोसा मायावती पर कायम है। वोट बैंक बिखरा, पार्टी की राजनीतिक जमीन भी खिसकती गई। बावजूद इसके मायावती की लोकप्रियता में गिरावट नहीं आई है। लखनऊ रैली में दलित समुदाय की भारी भागीदारी ने यह साफ कर दिया कि मायावती अब भी उनके लिए एक बड़ी नेता हैं। लंबे समय बाद किसी मंच पर मायावती को इस तरह आत्मविश्वास से भरे और उत्साहित अंदाज में बोलते देखना बसपा कार्यकर्ताओं के लिए भी एक सकारात्मक संकेत है। रैली में मायावती ने जहाँ योगी सरकार का आभार जताया वहीं समाजवादी पार्टी का अंधालि बता कर राजनीतिक गलियारे में चर्चा तेज कर दी। लेकिन अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए इसे सांठगांठ बता दिया। पिछली बार बसपा ने 2016 में बड़ी रैली की थी। उस रैली के बाद दो लोकसभा और दो विधानसभा हुए लेकिन बसपा को कोई फायदा नहीं हुआ। 2022 में मात्र एक सीट से बसपा को संतोष करना पड़ा। मायावती

अपने संबोधन के दौरान अखिलेश यादव और सपा पर सीधे हमलावर नजर आई और योगी सरकार की तारीफ भी की। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि कांशीराम पार्क और अंडेबकर पार्क में आने वाले लोगों से मिले टिकटों का पैसा योगी सरकार ने सपा सरकार की तरह दबाकर नहीं रखा। मेरे आग्रह पर पार्क की मरम्मत पर पूरा खर्च किया गया। जबकि सपा सरकार ने पार्क के रखरखाव की बजाय दूसरे मदों पर पैसा खर्च कर दिया था। मायावती ने भीम आर्मी के मुखूख और नगीना से सांसद चंद्रशेखर पर भी निशाना साधा और कहा कि हमें कमजोर करने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है। स्वार्थी और बिकाऊ किस्म के लोगों का इस्तेमाल करके कई संगठन बनवा दिए गए हैं। अब तो ये अंदर ही अंदर अपने वोट ट्रांसफर करवा कर इनके एक-दो उम्मीदवारों को जिता भी रहे हैं, जिससे दलित वोट बांटे जा सकें। मायावती ने मंच से अपने भतीजे आकाश आनन्द की तारीफ की और लोगों से आकाश का साथ देने की अपील भी की। मायावती ने सतीश चंद्र मिश्रा और उमके बेटे कपिल मिश्रा की भी तारीफ की। इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह, प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल और जमील अख्तर की भी जमकर सराहना की। और लोगों को भ्रमित न होने की बात कहते हुए उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने और 5वीं बार सरकार बनाने की भी बात करके कार्यकर्ताओं और समर्थकों में जोश भर दिया और सपा, भाजपा और कांग्रेस जैसे पार्टियों के षड्यंत्रों से सजग रहने की बात भी कही, इसके बाद सपा और भाजपा के अंदरखाने में भी चर्चा तेज हो गई है और



लोग मायावती को सत्ता तक न पहुँचने के लिए हर जुगत में जुट गए हैं क्योंकि भीड़ को देखकर सभी राजनीतिक पंडित भी हैरान हैं जो बसपा के प्रति आज भी लोगों का प्रेम और समर्थन दिखाता है।

रैली में मायावती के मंच पर लगी कुर्सियाँ और उसपर बैठे नेताओं ने सपा के पीड़ीए वाली राजनीति को समाप्त करने का बड़ा संकेत दे दिया। अभी तक इस तरह के मंच पर मायावती की ही कुर्सी विशेष होती थी लेकिन 9 अक्टूबर 2025 की रैली में मंच पर ब्राह्मण, ठाकुर, पिछड़ा, दलित और मुस्लिम चेहरे को एक साथ कुर्सी मिली जिसे बसपा की सोच में एक बड़ा बदलाव का संकेत माना जा रहा है। यह पहली बार था जब मायावती की किसी रैली में मंच पर दूसरे नेताओं को भी बैठने की जगह दी गई। विदित हो कि बसपा 2012 में यूपी की सत्ता से बाहर हुई थी। इसके बाद से पार्टी का ग्राफ लगातार गिरता गया। 2022 के चुनाव में सिर्फ एक विधानसभा सीट जीत पाई। वहीं, 2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा का खाता नहीं खुला। राजनीतिक जनकार मानते हैं बसपा को इस कार्यक्रम से बड़ी संजीवनी मिल सकती है। हालाँकि राजनीति में कब क्या हो जाये कोई कुछ नहीं कह सकता लेकिन बसपा की रैली में उमड़ी भीड़ ने तो राजनीतिक गालियारों में चचा तेज कर दी है।

संतोष कुमार तिवारी

इजरायल हमारा शांति समझौते के श्रेय के हकदार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप

इज़राइल और हमस के बीच शांतिवार्ता से से गाजा में शांति की रह खुली है।लोगो मे दहशतगर्दी और भय व्याप्त था।कब्रि,कब्रि वक्त मोत के आगो मे दब जाए,यह किसी को पता नही था।टम्प की पीसफुल वार्ता से हमस ही नही दुनिया मे खुशी का माहौल है।हमस भी इस समझौते को लेकर राजी है।नोबल पुरस्कार मिले, यह कौन नही चाहता है।नोबल पुरस्कार की बात पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शुहबाज शरीफ ने कही थी।तब से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को एक ही धुन सवार थी और वो किसी भी हालत में दो देशो के बीच शांति स्थापित करने की ठान ली ।मिस्र में लम्बी बातचीत के बाद इज़राइल और हमस के बीच युद्ध विराम के बाद हमस कैदियों को छोड़ने के लिए राजी हो गया है।गाजा की तुमाखी भरी जिद्द के कारण 18 हजार बच्चो की चीख-पुकार मलबे में दफन हो गई।120 हजार अनाथ हुए लोगो का जीना दुखार हो चुका है।इस बीच इज़राइल ने बहुत कुछ गवाया है।इज़रायल का 3.8 लाख करोड़ का खर्च हुआ है।युद्ध विनाश को निमंत्रण देता है।युद्ध मे दोनों देशो को नुकसान हुआ है।आज के बाद साल से चल रहे युद्ध को समझौता करके के बाद विराम लग गया है, लेकिन यह गारंटी के साथ नही कह सकते कि युद्ध खत्म हो ही जायेगा।दो सालों से इज़राइल और हमस के बीच काफी तनाव चल रहा है।हमस मे दोषय नही कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने मध्यस्थता करके दोनों देशों के बीच शांति वार्ता की सिफारिश करते हुए युद्ध विराम की घोषणा की गई है।लिहाज़ा, ट्रम्प ने दोनों देशों पर दबाव डालकर युद्ध रुकवाने की कोशिश की है।इसके साथ ही ट्रम्प वास्तविक नोबल पुरस्कार

के हकदार हैगाजा में ज़रून मनाया गया।अरब,इजराइल में खुशी का माहौल था।युद्ध हमारा ने शुरू किया था। दरअसल,2023 में हमारा ने इजराइल पर हमला किया था।उसमें 1,200 लोग मारे गए और 231 इजराइली को बंधक बना लिए गए थे।यह कर्तुत हमारी की थी।इजराइल सभी मुस्लिम देशों के बीच अकेला यहूदी देश है।टेक्नोलॉजी से भरपूर मिसाइलों का हमला हमला बहुत अधिक है।अचानक होने वाले हमले का जवाब मिसाइलें देती हैं।इजराइली की एक कनेड आबादी है।हैर्लिन वहां के वकनूत के हिसाब से पर के एक सदस्य को सेना में भर्ती होना पड़ा है।इजराइल के प्रधानमंत्री नेतयाहू का भी पतियार क्यों नहीं हो, उनके लड़के को भी देशसेवा के लिए एक वर्ष तक सेवा प्रदान करना पड़ा है।इजराइल के हमलों से गाजा का अधिकांश भाग नष्ट कर दिया है।हमारा की देश के किराड बहुत बड़ी भूल थी।हाइड हाउस में दोनों देशों के बीच सहमति बनने के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री नेतयाहू और डेनलड ट्रम्प सहित ने एक कार्यक्रम आयोजित में हिस्सा लिया।डेनलड ट्रम्प के दावा के बाद इजराइल को शांति वार्ता के लिए रजी होना पड़ा जबकि हमारा को भी ट्रम्प की बात का समर्थन करना पड़ा।युद्ध की विभीषिका मानवीय गुणों को नष्ट कर देती है।यहूदों को मानवीय की जानमारी की क्षति होती है।भारत ने पाकिस्तान के द्वारा किये गए युद्ध की संहार लीला से मोदी ने भूतकाल की याद ताजा की और उनका दिल पसीज गया । उन्होंने तब रूस और युक्रेन की जंग को खत्म करने का आग्रह कर कहा कि यह युद्ध का समय नहीं है।सभी देशों को मित्रक अरुन अपने अपने देश

के विकास में ध्यान देने की आवश्यकता है। गाजा में मानवीय सहायता बढ़ाई जाएगी।दोनो देशों में खुशी है।यहाँ तक युद्ध विराम के बाद भारत ने स्वागत किया है।दुनिया में पीस प्लान से खुशी व्याप्त है। दोनों देशों ने गंवाया ही गंवाया है।हासिल किसी को नहीं हुआ है।दो साल में 6 हजार लोगों की मौतें हुई है।दोनो देशों के बीच विस्थापन बहाली का पहला कदम साबित हुआ है।हाजबक शांतिवादी और युद्ध विराम का श्रेय डोनाल्ड ट्रम्प को जाता है।लम्बे समय से दोनों देशों के बीच युद्ध विराम को लेकर ट्रम्प आशावादी थे।यूक्रेन और रूस के प्रधानमंत्री को दूध ने शांति वार्ता के लिए मित्रपत्र दिया और युद्ध विराम के लिए दोनों देशों के रक्षाध्यक्ष को नियमों के अधीन समझावस की कोशिश की गई।शांती के मुनाफिक दोनों के बंधन को रिहा किया जाएगा।गाजा से इजरायल के सैनिक अधिकंश हट्टसे ले जायेंगे।युद्ध की विभीषिका जलते अंगारे की लौला है।दुसरे में सबकुछ खाक जलता जाता है।यह दुनिया के लिए भी विषटनकारी सिद्ध होता है।मानवता को ख़बरदार कर रख देता है।मिसाइल हमले विनाशकारी होते हैं।हाससे जमीनी की ऊर्क क्षमता नष्ट हो जाती है।युद्ध से मिसाइलों की गंध और किरणों से रोगों की उत्पत्ति होती है।इजरायली सेना से हवाई हमले किये और 30 लाख से ज्यादा लोग मारे गए।अदर असल, 17 लाख विस्थापित हो चुके है।यह अंकड़ बहुत बड़ है।गाजा की एक भूक के कारण लम्बे युद्ध ने लाखों हताहत हुए।2023 से जंग में सबसे ज्यादा फिलिस्तिनीयों की मौत हुई।इजरायली सेना ने गाजा के चरमपंथियों पर हमला किया गया।विनाश गाजा पट्टी में हुआ है।हाइमारे



जमींदोज हो चुकी है। मिसाइलों के हमले से गाजा पट्टी का भौगोलिक वातावरण बदल गया है। यही विनाश है। डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के बीच शांतिवार्ता में सहयोग कर दोनों देशों की

जमींदोज हो चुकी है। मिसाइलों के हमले से गाजा पट्टी का भौगोलिक वातावरण बदल गया है। यहाँ विनाफ है। डोनाल्ड ट्रम्प ने दोनों देशों के बीच शांति वार्ता में सहयोग कर दोनों देशों की खाई पाट दी है। हालाँकि पुस्तकार की चर्चा है और इसके लिए ट्रम्प हकदार है। गाजा पट्टी 1917 तक ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। प्राचीन व्यापारिक और समुद्री पट्टी पर स्थित एक तटीय पट्टी है। इजरायल और मिस्र से गाजा घिरा हुआ है। यहाँ ब्रिटिश हुकुमत का राज था और यह 1948 तक चला। इसके बाद मिस्र और इजरायल के कंट्रोल में रहा था। 1940 के दशक में यहाँ ब्रिटिश शासन का अंत हो गया। इसके बाद यहाँ दो अरबों के बीच जंग शुरू हो गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि मई 1948 में इजरायल का जन्म हुआ। जंग के दौरान हजारों फिलिस्तीनियों ने जान बचावे के लिए गाजा में शरण लिया। मिस्र की सेना ने युद्ध के समय गाजा पट्टी पर कंट्रोल कर लिया। उसका कंट्रोल काफी लंबे समय तक रहा और यहाँ आबादी भी बढ़ती चली गई। अब पीपुजन के बाद दुनिया में शांति का वातावरण बन रहा है। दुनिया में उन्हाह है।

कांतिलाल मांडोत

आस्था, विश्वास और विकास का पर्याय भारत

एक नई वैश्विक पहचान।
भारत में विगत दो-तीन दशकों में भारत में कृषि, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अतृप्तपूर्व प्रगति की है। भारत में विश्वे शी ली पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी तथा सामरिक क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाने में सफलता पाई है। इन दिनों विश्व में जितने भी राजनीतिक और कूटनीतिक अहम फैसले किजे जाते हैं उन में भारत की सलाह तथा उपस्थिति अनिवार्य माना जा रही है यह भारत के गौरव की बात है। 1947 में भारत और पाकिस्तान ने स्वतंत्रता प्राप्त की, लेकिन दोनों देशों की दिशा भिन्न रही। पाकिस्तान ने मुस्लिम राष्ट्र की अवधारणा अपनाई और अलग राह चुनी, जिसके परिणामस्वरूप आज वह कई आर्थिक और सामाजिक कठिनायों का सामना कर रहा है। भारत ने लोकतांत्रिक और जनतांत्रिक मूल्यों के आधार पर विकास के नए आयाम स्थापित किए, देश को सशक्त, विकसित और आत्मनिर्भर बनाया। पिछले दशक में भारत की राजनीतिक संरचना में उत्तरदायित्व आधारित शासन और प्रभावी प्रशासन ने लोकतंत्र को मजबूती दी। रिपोर्ट काई राजनीति के उदय ने नेताओं और दलों का

मूल्यांकन उनके कार्यों और परिणामों के आधार पर शुरू किया। संवैधानिक स्तर पर ऐतिहासिक कदम जैसे अनुच्छेद 370 का निरसन और जम्मू-कश्मीर का पुनर्गठन, तीन तलाक़ कानून और नागरिकता संशोधन अधिनियम ने न केवल राजनीतिक इच्छाशक्ति बल्कि सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय नीति में नए दृष्टिकोण स्थापित किए। डिजिटल संसदीय पहलें, ई-संसद और डिजिटलीकरण ने लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को तकनीकी रूप से सशक्त बनाया, वहीं विपक्ष, मीडिया और सोशल मीडिया ने लोकतांत्रिक विमर्श को चुनौतीपूर्ण और प्रभावशाली बनाया। नई भारत की अवधारणा केवल राजनीति और अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं रही। योग, आयुर्वेद और प्राचीन भारतीय ज्ञान को वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत किया गया। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भारतीय संस्कृति और धार्मिक आकांक्षाओं का प्रतीक बना। शिक्षा और पाठ्यपुस्तकों में भारतीय इतिहास और आख्यानो को नवीन रूप दिया गया। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के विकास पर जोर दिया गया। संस्कृतिक मंच-नीति के माध्यम से भारत ने वैश्विक संघ पर अपनी पहचान मजबूत की, जबकि बहुलतावाद

और परंपरा बनाम आधुनिकता जैसी सामाजिक चुनौतियाँ विचार विमर्श का विषय बनीं। भारत ने इस दशक में अर्थव्यवस्था में अभूतपूर्व सुधार किए। मेक इन इंडिया ने विनिर्माण और रक्षा उत्पादन को बढ़ावा दिया। जीएसटी ने कर प्रणाली को सरल और पारदर्शी बनाया, 2025 के संशोधन से आम जनता को बड़ी राहत मिली। डिजिटल इंडिया, जनधन योजना और PM ने नकदी रहित लेन-देन और वित्तीय समावेशन में क्रांति ला दी। स्टार्टअप इंडिया ने नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित किया। परिणामस्वरूप भारत विश्व की पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा, जबकि बेरोजगारी, ग्रामीण-शहरी असमानता और कृषि सुधार अधूरे रहना अभी भी गंभीर चुनौती बनी हुई है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत ने अपनी नई पहचान बनाई। G20 समिट और शंघाई सहयोग संगठन की बैठकों में भारत ने संतुलित और निर्णायक नेतृत्व प्रस्तुत किया। रूस, चीन और पड़ोसी देशों के साथ संतुलित कूटनीतिक संबंधों ने भारत



की स्थिति को मजबूत किया। अमेरिकी टैरिफ और यूरोपीय दबावों का भारत ने स्पष्ट विरोध किया, जिससे वैश्विक मंच पर उसकी भूमिका और प्रभाव बढ़ा। वाणिज्य की चुनौतियाँ और अवसर-पिछले दस वर्षों में राजनीतिक दृढ़ता, सांस्कृतिक आत्मगौरव और आर्थिक नवाचार ने भारत को वैश्विक परिदृश्य में निर्णायक शक्ति बना दिया।

इसके बावजूद असमानता, बेरोजगारी और राजनीतिक ध्रुवीकरण जैसी चुनौतियाँ बनी हुई हैं। सनातनी संस्कृति, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सामरिक शक्ति में वृद्धि ने भारतीय जनमानस की एकजुटता और नेतृत्व की कार्यकुशलता को बढ़ाया, जिससे भारत का सम्मान और कद विश्व स्तर पर ऊँचा हुआ।

संजीव ठाकुर

मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक रवि कुमार अवस्थी द्वारा सुशीला स्टेडी बेल एकेडमी 117-मोहल्ल विजय लक्ष्मी नगर परगना खैराबाद तहसील व जनपद-सीतापुर से प्रकाशित तथा महावीर आफसेट 28, हीवेट रोड लखनऊ से मुद्रित। सम्पादक रवि कुमार अवस्थी समाचार पत्र में छपे समस्त समाचार संवाददाताओं के अपने श्रोत एवं संकलन हैं, जिनसे सम्पादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। **नोट:-**उपरोक्त सभी पद अवैतनिक एवं स्वयंसेवी हैं तथा समाचार पत्र से सम्बंधित सारे विवादों का न्याय क्षेत्र सीतापुर होगा। **R.N.I.NO. UPHIN/2009/34814 मो० नं० -9511151254, E-Mail :- news@swatantraprabhat.com**

संपादकीय

मैं लड़की हूँ – संकट नहीं, समाधान हूँ!

बेटी अब प्रतीक्षा नहीं करती — वह
खुद इतिहास लिखती है
डिजिटल युग की बेटीयाँ-तकनीक
से बदलती दुनिया की दिशा
जब एक बालिका जन्म लेती है, वह
केवल एक जीवन नहीं लाती—वह एक नई
दृष्टि, अनंत संभावनाओं का सूर्य, और
समाज को बदलने की अटल शक्ति लाती
है। उसकी मुस्कान में भविष्य की गूँज और
आँखों में सपनों का सागर छिपा है। लेकिन

हल कटु सत्य भी है कि आज भी दुनिया के कई हिस्सों में वह भेदभाव, असमानता और अन्याय के साये में अपनी पहचान की लड़ाई लड़ रही है। अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस, जो हर साल 11 अक्टूबर को मनाया जाता है केवल एक तारीख नहीं, बल्कि एक क्रांतिकारी उद्घोषणा है—“मैं लड़की हूँ, मैं बदलाव की अगुआ हूँ।” यह दिन बालिकाओं की अदम्य शक्ति का उस्व है और उनके अनदेखे संघर्षों को सम्मान देने का आह्वान। संयुक्त राष्ट्र ने 2025 के लिए इस दिवस का विषय चुना है—“मैं लड़की हूँ।” बदलाव का नेतृत्व करती हूँ—संकट की अग्रिम पंक्ति में लड़कियाँ”, यह विषय आज की सच्चाई को उजागर करता है—बालिकाएँ अब परिवर्तन की प्रतीक्षा नहीं करती; वे उसकी सशक्त वाहक हैं। चाहे जलवायु परिवर्तन के खिलाफ संघर्ष हो, डिजिटल समाप्तता की मांग हो, या सामाजिक न्याय की लड़ाई—हर मोर्चे पर बालिकाएँ अपनी अमिट छाप छोड़ रही हैं। संकटों में, जब दुनिया ठहर जाती है, यही बालिकाएँ आगे बढ़ती हैं। कोविड-19 महामारी इसका जीवंत उदाहरण है। यूनेस्को के आंकड़ों के

के दौरान लड़कियों को
अक्सर परिवार की
जिम्मेदारियां उठानी
पड़ती हैं, जिससे उनकी
शिक्षा और स्वास्थ्य
प्रभावित होते हैं। लेकिन
यही लड़कियां समाधान
की मशाल भी थाम रही

मलावी और युगांडा में किशोरियां जलवायु कार्यकर्ता बनकर स्थानीय स्तर पर वृक्षारोपण और टिकाऊ खेती को बढ़ावा दे रही हैं। यह दिखाता है कि संकट की अग्रिम पंक्ति में लड़कियां केवल पीड़ित नहीं, बल्कि परिवर्तन की सशक्त अंगुली हैं। डिजिटल असमानता एक और अनदेखा संकट है। आज डिजिटल पहुंच केवल युवा नहीं, बल्कि मौलिक अधिकार हैं। फिर भी, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन (आईटीयू) के 2024 के आंकड़ों के अनुसार, विकासशील देशों में केवल 37% महिलाएं, विकासशील देशों में केवल 33% उपयोग करती हैं, जबकि पुरुषों के लिए यह आंकड़ा 43% है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल शिक्षा की कमी झेलनी पड़ती है। यह केवल तकनीकी संसाधनों की कमी नहीं, बल्कि सामाजिक सोच का अभाव है। केन्या और नाइजीरिया में लड़कियां डिजिटल शिक्षा के लिए अभियान चला रही हैं, कोडिंग सीख रही हैं, स्टार्टअप शुरू कर रही हैं, और तकनीकी क्षेत्र में अपनी जगह बना रही हैं। यह एक नई क्रांति की शुरुआत है, जो हमें यह सवाल पूछने को मजबूर करती है—क्या हम वाकई अपनी लड़कियों को डिजिटल युग में नेतृत्व के लिए सशक्त कर रहे हैं? लड़कियों का मानसिक दृढ़ता और आत्मविश्वास एक अमोल्य शक्ति है, जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। हम उन्हें सशक्त बनाने की बात करते हैं, लेकिन क्या हम उन्हें ठोकर खाकर फिर उठने का हौसला देते हैं? समाज लड़कियों से हर कदम पर अपाठता मांगता है, पर गलतियों से सीखने की पूजादाती उन्हें शायद ही मिलती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार, सामाजिक दबाव और लैंगिक असमानता के कारण किशोरियों में तनाव और चिंता की दर लड़कों से कहीं अधिक है। अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस हमें सिखाता है कि नेतृत्व का मतलब केवल जीत नहीं, बल्कि हर मुश्किल में खुद पर भरोसा कायम रखना है। हमें हर लड़की को यह यकीन दिलाना होगा कि उसकी आवाज अमूल्य है और उसकी

असफलताएं उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी शक्ति का सबूत हैं। परिवर्तन की शुरुआत घर की चौखट से होती है। ज्यादा परिवर्तन बेटीयों को निपटने वाले की आजदीक देते हैं? क्या उनकी राय को बेटीं जितना ध्यान देती हैं? क्या उनकी राय को बेटीं जितना ध्यान देती हैं? एक अध्ययन बताता है कि भारत में केवल 27% परिवार किशोरियों को घरलू फैसलों में शामिल करते हैं। नेतृत्व के लक्ष्य की नींव घर में पड़ती है। जब एक बेटी को नेतृत्व सपना मिलता है कि वह गलती कर सकती है, उससे सीख सकती है, और फिर दुनिया को चुनौती दे सकती है, तभी ऐसा सपना नेतृत्व निभाती है। हमें एक ऐसा समाज बनाना होगा जहां हर बालिका बिना डर के बोले, बिना बाधा के सीखे, और बेझिझक सपने सजाए। इसके लिए शिक्षा में समानता, रोजगार में समानता और सामाजिक ढांचे में संवेदनशीलता अनिवार्य हैं। लड़कियां अपने को मांग नहीं करती—वे बस खिलना चाहती हैं। वे ग्रेटा थनबर्ग की तरह जलवायु परिवर्तन के खिलाफ दुनिया को झकझोर रही हैं। वे डिजिटल युग में तकनीकी क्रांति की नींव रख रही हैं। वे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो अपने समुदायों में समानता को जोड़ रही हैं। "मैं लड़की हूँ, मैं बदलाव का नेतृत्व करती हूँ" सिर्फ एक नारा नहीं, एक अटल विश्वास है। यह हमें सिखाता है कि जब हम एक लड़की को बोलने का मंच देते हैं, तो हम भविष्य को बेधना शुरू करते हैं। जब हम उसकी प्रतिभा को प्रशंसित करते हैं, तो हम समाज को आगे बढ़ाते हैं। 11 अक्टूबर 2025 का अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस केवल एक तारीख नहीं, बल्कि एक क्रांति का आह्वान है। यह हर उस लड़की की आवाज को बुलंद कराता, जो अपने भीतर दुनिया बदलने की ज्वाला रखती है। जिस दिन हर लड़की अपनी भावनाओं को कह सके—"मैं डरती नहीं, मैं नेतृत्व करती हूँ"—वही दिन इस उसव की सच्ची जीत होगा। क्योंकि एक ऐसा समाज, जहां लड़कियां सच्यों में भी मुस्कुरा सकें, वही सच्चे सच्यों में प्रतिशोध है।

प्रो. आरके जैन

विश्व को अशांत करने वाले मांग रहे शांति का नोबेल पुरस्कार

आज के दौर में युद्ध और शांति का फार्मूला कुछ यूँ बदल गया है—पहले आग लगाओ, फिर पानी छिड़कने का बेंग करो, और अंत में “शांति दूत” की उपाधि खुद को दे दो। इस आधुनिक कुटनीति के सर्वश्रेष्ठ कलाकार नजर आते हैं वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति बिल डोनाल्ड ट्रम्प। आप वही व्यक्ति जो दावा करते हैं कि उन्होंने दुनिया में छह से ज्यादा युद्ध (भारत एवं पाकिस्तान; इजरायल और ईरान; अफ़्गानिस्तान और अज़रबैजान; कांगो और रवांडा; कंबोडिया और थाईलैंड; कोसावो और सर्बिया; हमारा और इजरायल; आदि) रुकवा कर शांति बहाल की हैं अतः उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाना चाहिए। कुछ देशों ने तो बाकायदा उनके नाम का विधिवत चयन समिति को प्रस्ताव भी भेज दिया। इसे इन देशों का डर कहो, या रणनीति या माननीय ट्रम्प के टैरिफ प्रेस को से बचने का तरीका। वास्तव में ट्रम्प के दूसरे कार्यकाल में प्रवेश करते ही विश्व की राजनीति और समीकरण बड़ी तेजी से बदल रही है। संप्रथम अवैधानिक रूप से कई वर्षों से रह रहे विदेशी नागरिकों को अपराधी की तरह अमेरिका से निकाला गया। उसके बाद रूस और यूक्रेन के मध्य लंबे समय से चल रहे युद्ध को रोकने के लिए माननीय पुतिन से वन टू वन मीटिंग की। इस मीटिंग से युद्ध तो रुक नहीं, अलबत्ता दोनों ओर से आक्रमण और तेज हो गये।

अनगिनत लाशें। विडंबना यह है कि जिस पाकिस्तान ने ओसामा को पनाह दी, जहां से पकड़ा गया, उसे आर्थिक और सैन्य सहायता देकर पुरस्कृत किया गया। दुनिया को अब समझना होगा कि अमेरिका का

MDCCC
 XXXIII
 C
 MDCCC
 XXVI

यूझाया युद्ध (भारत एवं पाकिस्तान; इजरायल और ईरान; आर्मेनिया और अज़रबैजान; कांगो और रवांडा; कंबोडिया और थाईलैंड; कोसोवो और सर्बिया; हमारा और इजरायल; आदि) रकबा कर शांति बहाल की है अतः उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाना चाहिए। कुछ देशों तो बाकायदा उनके नाम का विधिवत चयन समिति को प्रस्ताव भी भेज दिया। इसे इन देशों का डर कहे, या रणनीति या माननीय ट्रम्प के टैरिफ प्रकोप से बचने का तरीका। वास्तव में ट्रम्प के दूसरे कार्यकाल में प्रवेश करते ही विश्व की राजनीति और समीकरण बदलें तेजी से बदल रही है। सर्वप्रथम अवैधानिक रूप से कई वर्षों से रह रहे विदेशी नागरिकों को अपराधी की तरह अमेरिका से निकाला गया। उसके बाद रुस और यूक्रेन के मध्य लंबे समय से चल रहे युद्ध को रोकने के लिए माननीय पुतिन से वन टू वन मीटिंग की। इस मीटिंग से युद्ध तो रुकना नहीं, अलबत्ता दोनों ओर से आक्रमण और तेज हो गये।

युद्ध न रुकवा पाने का बदला या यूँ कहें खीझ भारत और चीन जैसे राष्ट्रों पर निकली, बढे हुए टैरिफ रेट के रूप में।मजददार बाद यह है कि यूक्रेन-रुस युद्ध के लिए केवल जिम्मेदार माना गया भारत की रुस से कच्चा तेल खरीदने की नीति को। अन्य देश भी रुस से तेल खरीद रहे थे पर दण्ड का भागी बना भारत और इस तरह शुरू हुआ एक अलग प्रकार का वार,जिसे 'टैरिफ वार' नाम दिया गया। अफगानिस्तान का नाम सुनते ही सभ्यता सिहर उठती है। ओसामा बिन लादेन की खोज में अमेरिका ने पूरा देश उजाड़ डाला, प्रजातांत्रिक सरकार का गला घोट दिया। "आतंक के खिलाफ युद्ध" के नाम पर बीस साल तक बारूद बरसाया, और जब थक गया तो पीछे छोड़ गया अस्थिर लोकतंत्र, अविवश्या और

"आतंकवाद विरोध" और "आतंक पोषण" एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इराक की त्रासदी की कहानी भी कुछ कम नहीं है। "विनाशकारी हथियार" खोजने निकली अमेरिकी सेना को हथियार तो नहीं मिले, पर पूरे देश को खंडहर में बदल दिया। फिर आतंकवाद समाप्ति के नाम पर हमस-इजराइल युद्ध का नया अध्याय शुरू हुआ। इसमें इजरायल को पूर्ण समर्थन और सहायता मिला। लग्ग की सरकार का इस लड़ाई में हमस लगभग खंडहर में बदल गया। जान-माल का भी ख़ुब नुकसान हुआ, बेकसूर नागरिक भी बेतहाशा मारे गये। पर्यावरण और इन्फ्रास्ट्रक्चर का भी बहुत क्षति पहुंची, मानवता की तार-तार हुई। अब ट्रम्प कर रहे हैं कि मैंने दोनों को युद्ध विराम के लिए राजी कर लिया है। अब मैं वहां विकास की नई कहानी लिखूंगा। ट्रम्प ने सक्ता प्राप्त करने के लिए आश्वसन दिया कि राष्ट्रपति बनते ही चंद दिनों में यूक्रेन-रूस युद्ध को समाप्त करवा दूंगा, विश्व में अमन-चैन के लिए काम करूंगा। प्रयास के नाम पर अमेरिका ने यूक्रेन को न सिर्फ घातक हथियार दिए अपितु नाटो देशों को भी अप्रत्यक्ष रूप से ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया।

हथियारों की मदद नहीं, आर्थिक भी हैं।
 चीन, यूरोप और भारत पर उन्होंने टैफ़स वॉर
 छेड़ें दी- कहा "अमेरिका आत्मनिर्भर
 बनेगा, नतीजा वैश्विक बाज़ारों में
 प्रभाव, महाद्वीपीय की सुनामी और अमेरिकी
 शटडाउन की नौबत। यह भी एक तरह का
 "आर्थिक युद्ध" ही था- फर्क बस इतना कि
 इसमें बारूद की जगह डॉलर बरसे। भारत
 भी इस "दोहरी शांति नीति" का साक्षी है।
 आतंकवाद पर दोहरे मापदंड, पकिस्तान की
 अप्रत्यक्ष सहयोग और दक्षिण एशिया में
 अस्थिरता फैलाना- सब "शांति" के नाम
 पर। जब भारत ने आतंक के खिलाफ़
 ऑपरेशन साइल चलाया, तो पश्चिमी राष्ट्र
 "संयम और संवाद" का प्रवचन देने लगे,
 पाकिस्तान के परमाणु हथियार सम्पन्न होने
 की दुहाई देने लगे, संयम का पाठ पढ़ाने लगे।
 और जब भारत ने आतंकी फ़िक्कों को
 नष्ट करने के उपरांत अभियान स्थगित
 किया, तो दुश्मन ने घोषणा कर दी- "मैंने दो
 परमाणु शक्तियों के बीच युद्ध रकवा
 दिया।" शायद कूटनीति का नया सिद्धांत
 दुहाई है- दूसरों के कर्म का श्रेय लेना और
 कैमरे के सामने मुस्कुराना। अब सवाल यह
 है- क्या शांति का नोबेल पुरस्कार उसी को
 देना पना चाहिए जो पहले युद्ध भड़काए, फिर
 शांति स्थापित करने की दुहाई दे? दुश्म शायद
 इस नए युग के सबसे सफल "युद्ध-शांति
 रणनीति" हैं। वे विनागरी भी लगाते हैं और
 "फिर हाथ के ऊपर खड़े होकर घोषणा भी
 करते हैं- "देखो, मैंने आग बुझा दी।" यदि
 यही शांति की परिभाषा है, तो इतिहास के
 हर युद्ध प्रिय शासक को मरणोपरान्त नोबेल
 पुरस्कार मिलना चाहिए- क्योंकि हर युद्ध के
 बाद कोई न कोई "विराम" तो आता ही है।
 फर्क बस इतना है कि वह विराम बारूद की
 शक्त और लाशों के ढेर पर टिका होता है।

डा मनमोहन प्रकाश

संक्षिप्त खबरें

सीसीबरगांव के पास गाई नदी तट में एक युवती का शव उद्धार इलाके में तनाव का माहौल है



असम धेमाजी। आज सुबह सीसीवर गांव से लगभग 4 किलोमीटर दूर गाई नदी के किनारे रेलवे पुल के पास एक 20 वर्षीय एक युवती का शव लावारिस हालत में मिला। पीड़िता की पहचान धेमाजी के



बिष्णुपुर के शीलआली माजगांव निवासी ज्योतिका कलिता के रूप में हुई है। पीड़िता का चेहरा काला पड़ा था और उसके मुंह से झाग निकल रहा था। शव के पास से एक हीरो स्कूटर (स्-22-च-2117) बरामद किया गया। शव के पास से एक हैंड बैग, कुछ नीली वस्तुएं और एक पानी की बोतल भी बरामद की गई। घटना स्थल से सीसीबरगांव पुलिस ने शव को उद्धार कर पोस्टमॉर्टम के लिए धेमाजी सिविल हॉस्पिटल भेज दिया गया। अब असली रहस्य पुलिस जाँच के बाद ही सामने आएगा इए हत्याकांड है या और कुछ।

57.44 लाख की धोखाधड़ी में शामिल दो आरोपी खुद थाने पहुंचे
दोनों ने पुलिस को 11 लाख रुपये सेंडर किये

मथुरा। थाना फरह पुलिस द्वारा पारसल शिपमेंट कम्पनी से षडयंत्र कर धोखाधड़ी कर चोरी करने वाले दो वांछित अभियुक्तों को किया गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 11 लाख रुपये बरामद किये गये हैं। नितिन पुत्र स्व. वेदप्रकाश निवासी गुण्डावली पतरामगेट निजर सुनारों की गौशाला भिवानी थाना भिवानी जिला भिवानी हरियाणा एवं विकास पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी खुशखेडा रोड प्रधान कालोनी नियर महाराजा पैलेस टपोखरा थाना टपोखरा जिला खैरतल तजारा राजस्थान को थाना परिसर से षडयंत्र कर धोखाधड़ी कर चोरी के 11 लाख रूपये के साथ किया गिरफ्तार। विधिक कार्यवाही करते हुये न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। 22 सितम्बर को अरुण, संजय सिंह व अन्य साथी नाम पता अज्ञात द्वारा षडयन्त्र कर धोखाधडी से शिकायतकर्ता शिपमेंट कम्पनी के 134 (इंटेल् प्रोसेसर) वास्तविक शिपमेंट्स (कीमत 57.44 लाख) को चोरी कर जाली नकली शिपमेंट्स से बदल देने के सम्बन्ध में थाने पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। 23 अक्टूबर को संजय सिंह पुत्र रेशमपाल सिंह व गोविन्द पुत्र डालचन्द को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था तथा विवेचना के दौरान सीडीआर अवलोकन, सीसीटीवी फुजेट, पृच्छाछ व अन्य साक्ष्य संलकन से नितिन व विकास अनुज, सोनू के नाम प्रकाश में आने पर थाना फरह पुलिस द्वारा उनके घरों का पता लगाकर तलाश किये जाने पर और न मिलने पर परिजनों को थाने पर प्रस्तुत करने के लिये बताये जाने पर नितिन व विकास अपने परिजनों के साथ थाने पर पहुंचे।

घाटमपुर सर्किल के 06 थाने में अक्वल

कानपुर नगर/घाटमपुर सर्किल के 06 थानों में जनसुनवाई,आईजीआरएस/पोर्टल में आई विभिन्न शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने में घाटमपुर सर्किल के 06 थाने प्रदेश में अक्वल रहे, घाटमपुर एसपी कृष्ण कान्त यादव ने सभी थाना प्रभारियों को जनसुनवाई का गुणवत्तापूर्ण समय से निस्तारण करने के निर्देश देने के साथ उनकी टीम को बधाई दी है, उन्होंने कहा कि आप सभी शिकायतों का समय से निस्तारण करें, घाटमपुर एसपी कृष्ण कान्त यादव ने बताया कि बीते सितंबर महीने के जनसुनवाई पोर्टल में आई विभिन्न शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए घाटमपुर सर्किल क्षेत्र के थाना सजेती, थाना घाटमपुर, थाना रेउना, थाना बिधनू, थाना साढ़, थाना सेन पश्चिम पारा को उरपर प्रदेश में प्रथम स्थान मिला है, कानपुर के घाटमपुर सर्किल क्षेत्र के सभी 06 थानों ने जनसुनवाई पोर्टल में मिलने वाली शिकायतों को गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया है, जिसके चलते सजेती, घाटमपुर,रेउना, बिधनू, साढ़,सेन पश्चिम पारा, थानों को 100 में 100अन प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, प्रदेश में आंकड़ा जारी होने के बाद घाटमपुर एसपी कृष्ण कान्त यादव ने थाना प्रभारियों और पुलिस कमियों को शिकायतों का समय से निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं, इसके साथ उन्होंने पूरी टीम को बधाई दी है, आपको बताते चलें कि अगस्त महीने में जनसुनवाई आईजीआरएस शिकायतों के निस्तारण में में घाटमपुर सर्किल के सजेगी,रेउना, बिधनू, साढ़, 100में 100 अंकों का अग्रिम प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है, वहीं सर्किल क्षेत्र के घाटमपुर और सेन पश्चिम पारा दूसरे स्थान पर रहे।

वाइट हाउस कमेटी को कोसता रह गया, इधर जीत के बाद मारिया कोरिना ने नोबेल प्राइज ट्रंप को ही किया समर्पित

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो ने शुक्रवार को नोबेल शांति पुरस्कार जीतने पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे वेनेजुएला के पीड़ित लोगों और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को समर्पित किया। मचाडो ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा सभी वेनेजुएलावासियों के संघर्ष को यह मान्यता हमारे कार्य को पूरा करने के लिए एक प्रोत्साहन है। उन्होंने इस समर्पण पर जोर दिया जिसकी ने उन्हें उम्मीद है कि अंतरराष्ट्रीय सहयोगियों से उन्हें आगे भी समर्थन मिलता रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि हम जीत की दहलीज पर हैं और आज, पहले से कहीं ज्यादा, हम राष्ट्रपति ट्रंप, संयुक्त राज्य अमेरिका की जनता, लैटिन अमेरिका की जनता और दुनिया के लोकतांत्रिक देशों पर भरोसा करते हैं, क्योंकि ये स्वतंत्रता और लोकतंत्र हासिल करने के हमारे प्रमुख सहयोगी हैं।

मचाडो ने यह पुरस्कार अपने साथी नागरिकों को समर्पित किया और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का भी आभार व्यक्त किया।

श्रीभूमि जिले के रामकृष्णनगर में पहली बार स्वास्थ्य सेवा के %मेधा हेल्थ कैंप% का आयोजन किया गया

● 50 से अधिक बीमारियों की पूर्ण जांच, निदान और उन्नत चिकित्सा तथा मुफ्त दवाओं का वितरण किया गया।

हिमन्त विश्व शर्मा के नेतृत्व में असम में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हो रहा है- विधायक विजय ने कहा।

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

असम के मुख्यमंत्री के सपनों की स्वास्थ्य सेवा परियोजना के अंतर्गत असम के विभिन्न क्षेत्रों में बहुप्रतीक्षित 'मेधा हेल्थ कैंप' का आयोजन किया जा रहा है। इस टपोखरा जिला खैरतल तजारा राजस्थान को थाना परिसर से षडयंत्र कर धोखाधड़ी कर चोरी के 11 लाख रूपये के साथ किया गिरफ्तार। विधिक कार्यवाही करते हुये न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। 22 सितम्बर को अरुण, संजय सिंह व अन्य साथी नाम पता अज्ञात द्वारा षडयन्त्र कर धोखाधडी से शिकायतकर्ता शिपमेंट कम्पनी के 134 (इंटेल् प्रोसेसर) वास्तविक शिपमेंट्स (कीमत 57.44 लाख) को चोरी कर जाली नकली शिपमेंट्स से बदल देने के सम्बन्ध में थाने पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। 23 अक्टूबर को संजय सिंह पुत्र रेशमपाल सिंह व गोविन्द पुत्र डालचन्द को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था तथा विवेचना के दौरान सीडीआर अवलोकन, सीसीटीवी फुजेट, पृच्छाछ व अन्य साक्ष्य संलकन से नितिन व विकास अनुज, सोनू के नाम प्रकाश में आने पर थाना फरह पुलिस द्वारा उनके घरों का पता लगाकर तलाश किये जाने पर और न मिलने पर परिजनों को थाने पर प्रस्तुत करने के लिये बताये जाने पर नितिन व विकास अपने परिजनों के साथ थाने पर पहुंचे।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. राजेश मिश्रा ने जानकारी दी

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

बुढ़ार, शहडोल है कि राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम अन्तर्गत भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा तम्बाकू युवा मुक्त अभियान 3.0 का शुभारंभ प्रधामंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा 09 अक्टूबर 2025 को किया गया। उन्होंने बताया कि तम्बाकू मुक्त युवा जन जागरूकता अभियान 60 दिवस तक पूरे जिले में संचालित किया जाएगा। जिसका मुख्य उद्देश्य युवा वर्ग को तम्बाकू एवं तम्बाकू से बने उत्पाद, सिगरेट आदि के सेवन से होने वाले स्वास्थ्य नुकसान की जानकारी देकर तम्बाकू का उपयोग नहीं करने की समझाइस देकर स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना है। उन्होंने बताया कि तम्बाकू के सेवन से कैंसर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर व अन्य जानलेवा बिमारियों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. राजेश मिश्रा ने बताया कि तम्बाकू मुक्त युवा वर्ग 3.0 अभियान के अन्तर्गत युवा वर्ग को जागरूक करने शिक्षा विभाग, पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग, पुलिस

घाटमपुर में ब्लाक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता संपन्न

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

कानपुर नगर/घाटमपुर के साढ़ में ब्लाक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, यहां पर छात्र छात्राओं ने अपनी प्रतिभा दिखाई, प्रतियोगिता में अक्वल आए छात्र छात्राओं को ब्लाक प्रमुख भीतरगांव अशोक सचान के द्वारा प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया, साढ़ थाना क्षेत्र के बारी गांव स्थित सीएल मेमोरियल इंटर कालेज में भारत कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के तहत दो दिवसीय ब्लाक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बालिका वर्ग में,रस्साकसी, वौडू और बैडमिंटन,बालक वर्ग में वालीबाल, वौडू, लंबी कूद,का आयोजित किए गए, प्रतियोगिता में सफल खिलाड़ियों को



उन्होंने कहा कि मैं यह पुरस्कार वेनेजुएला के पीड़ित लोगों और हमारे मुद्दे के प्रति उनके निर्णायक समर्थन के लिए राष्ट्रपति ट्रम्प को समर्पित करती हूँ। नॉर्वेजियन नोबेल शिफ्ट विषण्णा की कि वह 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार डोनाल्ड ट्रम्प के बजाय मारिया कोरिना मचाडो को देगी, तो व्हाइट हाउस ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति शांति समझौते करना, युद्ध समाप्त करना और जीवन बचाना जारी रखेंगे। व्हाइट हाउस के संचार निदेशक ने एक्स पर लिखा राष्ट्रपति ट्रम्प शांति समझौते करते रहेंगे, युद्ध समाप्त करते रहेंगे और लोगों की जान बचाते रहेंगे। उनका दिल मानवतावादी है, और उनके जैसा कोई नहीं होगा जो अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति से पहलों को हिला सके। हालाँकि, व्हाइट हाउस ने नोबेल समिति पर कटाक्ष करते



प्रशासन स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि, विभिन्न विभागों के अधिकारी, राजनीतिक नेता, स्थानीय गण्यमान्य व्यक्ति और पंचायत प्रतिनिधियोग मौजूद थे।

बैठक में रामकृष्ण नगर लोकप्रिय विधायक विजय मालाकार ने कहा कि 0 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए इस शिविर में सभी प्रकार की बीमारियों का पूर्ण परीक्षण, आवश्यक चिकित्सा और दवाइयों प्रदान की जा रही हैं। आवश्यकता पड़ने पर उन्नत चिकित्सा के लिए रेफरेंस सुविधा भी दी जा रही है। उन्होंने और कहा कि लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व में असम में स्वास्थ्य सेवाएं उच्च गुणवत्ता की हो रही हैं। निःशुल्क विधानसभा आधारित मेगा स्वास्थ्य शिविर में हृदय रोग, स्नायु रोग से लेकर आँख और कान संबंधित समस्याओं सहित 50 से अधिक बीमारियों की पूर्ण स्क्रीनिंग, निदान और चिकित्सा की जाती है। विशेष रूप से गरीब वर्ग में रहने वाले व्यक्तियों में छट्ट छट्ट का र्द का वितरण हमारी सर्वांगीण और सुलभ स्वास्थ्य सेवा के वादे को और मजबूत करेगा और मुख्यमंत्री के इस स्वास्थ्य सेवा परियोजना को शुश्रूषा सेतु परियोजना के माध्यम से सफलतापूर्वक लागू करना हमारा कर्तव्य है।



विभाग, स्वास्थ्य विभाग आदि के समन्वय व सहभागिता तथा सक्रिय सहयोग से चलाया जाना है। इस अभियान के जिला नोडल अधिकारी डॉ. पुनीत श्रीवास्तव बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री जी के तम्बाकू मुक्त स्वस्थ भारत के निर्माण का संकल्प पूरा किया जायेगा। इस अभियान के अन्तर्गत जिला, विकासखण्ड तथा ग्राम स्तर पर जन जागरूता अभियान चलाकर ग्रामों को तम्बाकू मुक्त बनाने का संकल्प पूरा किया जायेगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने जिले के सभी जनप्रतिनिधियों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं, समाजसेवीयों तथा इलक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मिडिया तथा सहयोगी विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों से अपील की है कि राष्ट्र निर्माण के इस वर्ग को जागरूक करने शिक्षा विभाग, पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग, पुलिस

हुए कहा कि उन्होंने शांति के स्थान पर राजनीति को चुना। डोनाल्ड ट्रम्प ने अभी तक मारिया कोरिना मचाडो की नोबेल जीत पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। हालाँकि, अमेरिकी राष्ट्रपति ने अतीत में मचाडो और उनके सहयोगियों के लोकतंत्र आंदोलन का समर्थन किया है। इस वर्ष जनवरी में, जब वेनेजुएला के कराकस में निकोलस मादुरो के खिलाफ सरकार विरोधी प्रदर्शन के दौरान मचाडो को कुछ समय के लिए हिरासत में लिया गया था, तो ट्रम्प ने उनकी सुरक्षा की मांग की थी। वेनेजुएला के विपक्ष के साथ-साथ अमेरिका ने भी कथित तौर पर कहा था कि मादुरो ने 2024 के राष्ट्रपति चुनाव को चुरा लिया है, और तर्क दिया था कि मचाडो द्वारा समर्थित एडुमुंडो गोंजालेज ही असली विजेता थे।



इसके लिए पत्रकार, प्रशासन, स्वास्थ्यकर्मों, स्थस्थानीय जनप्रतिनिधि और आम नागरिक, सभी से सहयोग की कामना करते हैं। विशेष रूप से बारक के 31 विशेषज्ञ चिकित्सक, पैरा मेडिकल स्टाफ, नर्स, स्थानीय नागरिक और स्वयंसेवी संगठनों के प्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त किया। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का कहना है कि रामकृष्णखर आम जन के घर तक उन्नत चिकित्सा पहुँचाने के इस प्रयास को ऐतिहासिक कदम के रूप में देखा जा सकता है। आयोजकों ने बताया कि शिविर में विभिन्न विशेषज्ञ चिकित्सक दल भाग लिया। आधुनिक उपकरणों के माध्यम से रोगों का निदान करने से लेकर चिकित्सा परामर्श तक सभी प्रकार की सुविधाएँ रोगियों के लिए उपलब्ध कराई गई हैं।

त्योहारों को देखते हुये एस पी नें चलाया सघन वैकिंगओर तलाशी अभियान
बस्ती। बस्ती जिले मेंआगामी त्योहारों के मद्देनजर जनपदीय पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कम्प कस ली है। त्योहारों को सकुशल एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से जिले भर में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक बस्ती अभिनंदन ने गुरुवार को स्वयं रेलवे स्टेशन पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने पुलिस बल के साथ रेलवे स्टेशन पर पैदल मार्च किया और आसपास के क्षेत्रों में चेकिंग अभियान का निरीक्षण किया।इस दौरान एसपी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि त्योहारों के समय किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी थाना क्षेत्रों में नियमित गश्त को बढ़ाया गया है, सदिध व्यक्तियों की गहन चेकिंग की जा रही है और भीड़भाड़ वाले इलाकों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। उन्होंने कहा कि त्योहारों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक तैयारी की गई है। एसपी ने नागरिकों से अपील की कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी सदिध गतिविधि या वस्तु की जानकारी तुरंत पुलिस को दें ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।

बस्ती। बस्ती जिले मेंआगामी त्योहारों के मद्देनजर जनपदीय पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कम्प कस ली है। त्योहारों को सकुशल एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से जिले भर में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक बस्ती अभिनंदन ने गुरुवार को स्वयं रेलवे स्टेशन पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने पुलिस बल के साथ रेलवे स्टेशन पर पैदल मार्च किया और आसपास के क्षेत्रों में चेकिंग अभियान का निरीक्षण किया।इस दौरान एसपी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि त्योहारों के समय किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी थाना क्षेत्रों में नियमित गश्त को बढ़ाया गया है, सदिध व्यक्तियों की गहन चेकिंग की जा रही है और भीड़भाड़ वाले इलाकों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। उन्होंने कहा कि त्योहारों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक तैयारी की गई है। एसपी ने नागरिकों से अपील की कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी सदिध गतिविधि या वस्तु की जानकारी तुरंत पुलिस को दें ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।



आयोजन किया जा रहा है,इस अवसर पर प्रधानाचार्य श्रीपाल कुशवाहा, प्रबंधक रेखा कुशवाहा, अध्यक्ष रामनाथ कुशवाहा, एडवाइजर पद से प्रांजल कुमार,रेफरी शशि प्रकाश, अमित, विवेक शुक्ला, विकास, और अन्य लोगों से रमेश यादव, रमाशंकर, रवीपाल, सतीश, सौरभ, कौशल, राहुल, प्राची, आकांक्ष अनुष्का, आकांक्षा शुक्ला एवं विभिन्न युवा मंडल के लोग मौजूद रहे।

घाटमपुर के श्रीनगर में खुले नाले से खतरा, जिम्मेदार मौन



कानपुर नगर/घाटमपुर ब्लाक के श्रीनगर गांव में एक खुला नाला स्थानीय निवासियों और राहगीरों के लिए खतरा बना हुआ है, दो साल पहले इसका निर्माण शुरू हुआ था, लेकिन यह अधूरा छोड़ दिया गया, जिससे लोगों के गिरने का जोखिम बढ़ गया है, ग्राम पंचायत श्रीनगर ने मुगल रोड से सजेती मार्ग पर लगभग 24 लाख रूप की लागत से 300 मीटर आरसीसी सड़क और नाली का निर्माण कराया था, लेकिन नाले का काम अधूरा रह गया, जिससे यह खुला और क्षतिग्रस्त स्थित में है,इस मार्ग से प्रतिदिन लगभग 1500 लोगों का आवागमन होता है, जिनमें स्कूली बच्चे भी शामिल हैं,खुले नाले के कारण उनके लिए दुर्घटना का खतरा बना रहता है, गांव निवासी दिनेश सिंह टिल्लू, धर्मेन्द्र,विनोद और मनोज सिंह ने बताया कि उन्होंने दो साल पहले भी ग्राम सचिव से नाले के निर्माण की शिकायत की थी, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई,इस मामले पर ग्राम पंचायत सचिव चंद्रकार ने बताया कि नाले का सेंस पूरा हो चुका है और इसका निर्माण कार्य जल्द ही शुरू करा दिया जाएगा।

इंडस्ट्री एरिया में छापा, 7.37 लाख का तेज फैट सीज किया

● खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने दो दिन चलाया अभियान

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

मथुरा। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने दीपावली पर्व के दृष्टिगत मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी ज्ञानपाल सिंह के नेतृत्व में खाद्य सचल दल दो दिन का अभियान चला कर कुल 12 खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए। वृन्दावन से सांभर व पेड़ का एक एक नमूना, बल्देव से सरसों का तेल का एक नमूना, होलीगेट से घी का एक नमूना, टाउनशिप से शिल्क केक का एक नमूना, नौहशील से घी का एक नमूना, बाजना से मिश्रित दूध के दो नमूने तथा बिना खाद्य अनुज्ञप्ति प्राप्त कर संचालित इण्डस्ट्रियल एरिया स्थित निर्माण इकाई से रिफाइनड सोयाबीन आबल का एक नमूना तथा इंटरएस्टेरीफाइट वेज

आगामी त्योहारों के मद्देनजर महाराजगंज तराई पुलिस द्वारा किया गया पैदल गस्त

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

बलरामपुर/महाराजगंज तराई पुलिस अधीक्षक बलरामपुर द्वारा जनपद में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, स्वालंबन और सशक्तिकरण हेतु चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान (फेज-5.0)के अंतर्गत आज महाराजगंज तराई दीपावली की त्योहार को देखते हुए पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक विशाल पांडे के मार्गदर्शन क्षेत्र अधिकारी ललिया देवेंद्र कुमार की पर्यवेक्षण में थाना अध्यक्ष महाराजगंज अखिलेश पांडे के नेतृत्व में चौराहा कस्बा का पैदल गस्त किया गया व जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों का आयोजन स्कूलों, कालेजों तथा बाजारों में किया गया, जहाँ बालिकाओं को आत्मनिर्भर और जागरूक बनाने के उद्देश्य से संवाद

921 का था बिल 66 हजार का भेज दिया नोटिस

● किसान संगठन के हंगामे के बाद माना विभाग

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

मथुरा। बिजली विभाग की महिला उपभोक्ता पर 921 का बिजली का बिल बकाया था। विभाग की ओर से उपभोक्ता को 66 हजार का नोटिस भेज दिया गया। किसान संगठन ने जब बिजली घर पर हंगामा काटा तो विभागीय अधिकारियों ने बिल को 921 ही मान और उपभोक्ता ने राहत की सांस ली। भारतीय किसान यूनियन चौधरी चरण सिंह संगठन के जिला अध्यक्ष गजेन्द्र सिंह के नेतृत्व में किसानों ने बिजली घर कैट का घेराव किया गया। यहां किसान और मजदूर की समस्याओं को उठाया गया। शिकायत की गई कि किसानों को 22 घंटे लाइट मिलनी चाहिए जो कि नहीं मिल रही है। लंबे लंबे पावर कट लगाए जा रहे हैं बिजली बिल स्मार्ट मीटर लगने के बाद में

कप्तान स्कूल बुढ़ार में किया गया विधिक जागरूकता शिविर



स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

शहडोल मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के मार्गदर्शन तथा माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष महोदय श्री काशीनाथ सिंह, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शहडोल के निर्देशन में एवं श्री सुशील कुमार अग्रवाल जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति, बुढ़ार एवं श्री विजेंद्र सिंह रावत एवं श्री लक्ष्मण रोहित व्यवहार की थी, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई,इस मामले पर ग्राम पंचायत सचिव चंद्रकार ने बताया कि नाले का सेंस पूरा हो चुका है और इसका निर्माण कार्य जल्द ही शुरू करा दिया जाएगा।

उक्त शिविर में उपस्थित छात्र-छात्राओं को कानून से संबंधित जानकारी, पॉक्सो एक्ट, सिविलान से संबंधित प्रश्न/वातालाप डिजिटल अर्रेस्ट, मौलिक अधिकार, एवं अन्य विषयों में जागरूक किया गया। शिविर में कप्तान स्कूल एवं कन्या हायर सेकेंडरी के प्राचार्य डॉ0 देवेन्द्र श्रीवास्तव, व शिक्षक राम गोपाल मिश्रा, श्रीमती कविता पयासी डॉ. शाइस्ताजबी सिद्दीकी, श्रीमती रश्मि शुक्ला, अशोक भुमिया, शैलेंद्र कुमार गर्ग, श्रीमती साधना शर्मा, श्रीमती सीमा अग्रवाल, राकेश कुमार गुप्ता, बद्री प्रसाद साहू, श्रीमती नीतू सिंह, श्रीमती मीरा शर्मा एवं विधिक सेवा समिति न्यायालय बुढ़ार से संबद्ध सामाजिक कार्यकर्ता अभिषेक मुखर्जी उपस्थित रहे।



खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम कार्यवाही करते हुए।
फैट के तीन नमूने संग्रहित कर शेष बचे लगभग 3957 लीटर इंटरएस्टेरीफाइट वेज फैट जिसका मूल्य 7,37,715 को सीज किया गया। खाद्य सचल दल में राम नरेश, जितेंद्र सिंह, दलबीर सिंह, अरुण कुमार, रीना शर्मा, मोहर सिंह कुशवाहा, भरत सिंह एवं धर्मेन्द्र सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी शामिल रहे। इसके अतिरिक्त रीना शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा एफ.एस.डब्लू (सचल खाद्य प्रयोगशाला) वाहन के माध्यम से वृन्दावन स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय में आई.ई.सी. कार्यक्रम आयोजित कर अध्ययनरत

स्थापित किया गया। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं एवं बालिकाओं को विभिन्न उपयोगी हेल्पलाइन नम्बरों जैसे-वूमैन पॉवर लाइन-1090, पुलिस आपातकालीन सेवा-112, एम्बुलेंस सेवा-108, चार्लड लाइन-1098, स्वास्थ्य सेवा-102, महिला हेल्पलाइन-181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1076 तथा साइबर हेल्पलाइन-1930 की विस्तृत जानकारी दी गई। इसके साथ ही गुड टच-बैड टच, घरेलू हिंसा, साइबर अपराध, महिला अधिकारों एवं कानूनी प्रावधानों के विषय में सार्थक चर्चा की गई। उपस्थित जनसमूह को शासन द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई तथा पम्पलेट वितरण कर जागरूक किया गया। इसी क्रम में स्थानीय थानों पर नवस्थापित मिशन शक्ति केन्द्र के कार्य, उद्देश्य तथा वहां उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं की भी

जानकारी प्रदान की गई, ताकि महिलाएं और बालिकाएं अपनी समस्याओं के समाधान हेतु इन सेवाओं का लाभ उठा सकें। इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं एवं बालिकाओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना, उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना तथा आत्मनिर्भरता की दिशा में अग्रसर करना है। पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं, जिनसे समाज में महिलाओं की सुरक्षा एवं सम्मान सुनिश्चित किया जा सके।

921 का था बिल 66 हजार का भेज दिया नोटिस



कैट बिजली घर पर विरोध प्रदर्शन करते किसान संगठन के कार्यकर्ता।
बहुत ज्यादा आ रहे हैं। 70 स्कॉयर फीट के हिसाब से कनेक्शन किया जा रहा है। जो कि गरीब और किसानों के लिए बहुत मुश्किल है। सविता रावत औरंगाबाद का बिल जो कुछ 66 हजार रुपए बिजली विभाग के द्वारा बताया गया था। भारतीय किसान यूनियन चौधरी चरण सिंह संगठन के जिला अध्यक्ष मथुरा गजेन्द्र सिंह ने साथ दिया तो 921 रुपये सविता रावत का बिजली विभाग पर बकाया दिखाया गया।बिजली विभाग एसडीओ को जापन दिया गया। जापन में देने के दौरान सदीप हिंडोल राष्ट्रीय सचिव, सीमा शर्मा प्रदेश प्रवक्ता, पवन चौधरी प्रदेश महासचिव आगरा, रंजेंद्र गुर्जर



जिला अध्यक्ष आगरा, गजेन्द्र सिंह, ठा वेद पाल सिंह तोमर, अनिल शर्मा, प्रवीण चौधरी, धर्मेन्द्र सिकरवार, बीके चौधरी, जीतू पांडे, कुलदीप सविता रावत औरंगाबाद का बिल जो कुछ 66 हजार रुपए बिजली विभाग के द्वारा बताया गया था। भारतीय किसान यूनियन चौधरी चरण सिंह संगठन के जिला अध्यक्ष मथुरा गजेन्द्र सिंह ने साथ दिया तो 921 रुपये सविता रावत का बिजली विभाग पर बकाया दिखाया गया।बिजली विभाग एसडीओ को जापन दिया गया। जापन में देने के दौरान सदीप हिंडोल राष्ट्रीय सचिव, सीमा शर्मा प्रदेश प्रवक्ता, पवन चौधरी प्रदेश महासचिव आगरा, रंजेंद्र गुर्जर

जिलाधिकारी द्वारा सिकटिया पीएचसी का किया औचक निरीक्षण

कानपुर नगर/घाटमपुर जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने शुक्रवार को सिकटिया स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पीएचसी का औचक निरीक्षण किया,इस दौरान केंद्र पर लैब उपकरण न होने का मामला सामने आया है,जिस पर जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्साधिकारी कोई15 दिनों के भीतर सभी आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, निरीक्षण के दौरान तीनों स्वास्थ्य कर्मी अपनी ड्यूटी पर मौजूद पाए गए,और ओपीडी नियमित रूप से संचालित हो रही है और मरीजों को उपस्थित और उपचार व्यवस्था देखकर जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने संतोष व्यक्त किया, इलाज के लिए पहुंची मरीज श्यामकली, और रेखा, सहित अन्य लोगों ने पीएचसी की चिकित्सक डॉ पुनम सिंह की सराहना की, मरीजों ने डीएम को बताया कि डॉ नियमित रूप से समय पर उपस्थित रहती हैं, और सभी का इलाज पूरी निष्ठा व सेवा भाव से करती हैं,किसी प्रकार की लापरवाही न ही करती हैं, मरीजों की बातें सुनने के बाद जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने प्रसन्नता व्यक्त की और चिकित्सक को बेहतर कार्य बनाए रखने के निर्देश दिए, डीएम ने दवा वितरण व्यवस्था की भी जानकारी दी, उन्होंने मरीजों और परिजनों से पूछ कि क्या उन्हें दवाएं समय से मिलती हैं,इस पर सभी ने संतोष जनक उत्तर देते हुए बताया कि उन्हें दवा निश्चित समय पर मिलती हैं, जिला प्रशासन की टीम ने लैब जांच व्यवस्था का जाला लगा,इस दौरान जानकारी मिली कि केंद्र पर लैब टेक्नीशियन सदीप कुमार तो तैनात हैं, लेकिन आवश्यक उपकरणों के अभाव में पैथालाजिकल जांच का कार्य नहीं हो पा रहा है,इस स्थिति में मुख्य चिकित्साधिकारी को सख्त निर्देश दिए कि आगामी 15 दिनों के भीतर सभी जरूरी उपकरण उपलब्ध कराए जाएं, निरीक्षण के समय जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने स्वास्थ्य केंद्र की साफ सफाई, रजिस्ट्ररों के रखरखाव और कर्मचारियों की उपस्थिति का भी बारीकी से जायजा लिया।